Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

NCCT CO-OP NEWS BULLETIN

Date: 06.02.2024

Sr No	Date	Publication	Edition	Page no.
1.	06-02-2024	Aaj Samaj	Karnal	2
2.	06-02-2024	Chirag Times	Hisar	4
3.	06-02-2024	Haryana Today	Hisar	2
4.	06-02-2024	Agri2047	Online	

Publication:	Aaj Samaj, Pg 2	Edition: Karnal	Print
Published Date:	February 06, 2024		

बजट 2024 किसानों को सशक्त बनाएगा; सहकारी समितियों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होगी अहम भूमिका

करनाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण के अनुरूप, अंतरिम बजट 2024 सहकारी क्षेत्र के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की पहल को प्राथमिकता देता है। संसद में प्रस्तुत बजट गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई 54 प्रमुख पहलों को प्रतिबिंबित करता है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहल का उद्देश्य देश भर में पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) और प्राथमिक सहकारी समितियों को मजबूत करना है, जो ग्रामीण समृद्धि की राह पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जबकि बजट विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलों के माध्यम से महिलाओं सशक्तिकरण, युवाओं, हाशिए पर रहने वाले समूहों और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रणालीगत असमानता में कमी को प्राथमिकता देता है, यह सहकारी समितियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी काफी बढ़ावा देता है। बजट के विभिन्न पहलुओं को समझाते हुए, अधिकारियों ने कहा कि डेयरी प्रसंस्करण, ब्रांड निर्माण, विपणन और बुनियादी ढांचा विकास (डीआरडीएफ) फंड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के लिए निरंतर समर्थन सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूत करता है। सरकार का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से लखपति दीदियों की संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना है और इस उद्देश्य के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया है। अधिकारियों ने कहा कि चूंकि ग्रामीण स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को पैक्स द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, इसलिए यह पैक्स के लिए ग्रामीण स्तर पर इसे लागू करके ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। बजट में कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों और मत्स्य पालन को प्राथमिकता दी गई है, किसान सहकारी समितियों और मूल्य संवर्धन पर जोर दिया गया है। यह ग्रामीण ऋण को मजबूत करने की पिछली पहलों पर आधारित है, जिसमें पैक्स को ग्रामीण समृद्धि के लिए बहु-सेवा केंद्र के रूप में देखा गया है। बजट का एक अन्य प्रमुख पहलू यह है कि इसमें सहकारी मत्स्य पालन क्षेत्र के लाभ के लिए देश में पांच एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है।

Publication:	Chirag Times, Pg 4	Edition: Hisar	Print
Published Date:	February 06, 2024		

बजट 2024 किसानों को सशक्त बनाएगा; सहकारी समितियों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होगी अहम भूमिका

हिसार (चिराग टाइम्स)

हिसार / बजट 2024 किसानों को सशक्त बनाएगा; सहकारी समितियों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होगी अहम भूमिका

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप, अंतरिम बजट 2024 सहकारी क्षेत्र के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की पहल को प्राथमिकता देता है। संसद में प्रस्तुत बजट गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई 54 प्रमुख पहलों को प्रतिबिंबित करता है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहल का उद्देश्य देश भर में पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) और प्राथमिक सहकारी समितियों को मजबूत करना है, जो ग्रामीण समृद्धि की राह पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

जबकि बजट विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलों के माध्यम से महिलाओं सशक्तिकरण, युवाओं, हाशिए पर रहने वाले समूहों और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रणालीगत असमानता में कमी को प्राथमिकता देता है, यह सहकारी समितियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी काफी बढ़ावा देता है।

अधिकारियों ने कहा कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने से पैक्स की विविध गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास को और बढ़ावा मिलता है

Publication:	Haryana Today, Pg 2	Edition: Hisar	Print
Published Date:	February 06, 2024		

बजट 2024 किसानों को सशक्त बनाएगा, सहकारी समितियों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होगी अहम भूमिका

हिसार टुडे। हिसार

बजट 2024 किसानों को सशक्त बनाएगा; सहकारी समितियों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होगी अहम भूमिका प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण के अनुरूप, अंतरिम बजट 2024 सहकारी क्षेत्र के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की पहल को प्राथमिकता देता है। संसद में प्रस्तुत बजट गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई 54 प्रमुख पहलों को प्रतिबिंबित करता है।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहल का उद्देश्य देश भर में पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) और प्राथमिक सहकारी समितियों को मजबूत करना है, जो ग्रामीण समृद्धि की राह पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जबकि बजट विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलों के माध्यम से महिलाओं सशक्तिकरण, युवाओं, हाशिए पर रहने वाले समूहों और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रणालीगत असमानता में कमी को प्राथमिकता देता है, यह सहकारी समितियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी काफी बढ़ावा देता है। बजट के विभिन्न पहलुओं को समझाते हुए, अधिकारियों ने कहा कि डेयरी प्रसंस्करण, ब्रांड निर्माण, विपणन और बुनियादी ढांचा विकास (डीआरडीएफ) फंड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के लिए निरंतर समर्थन सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूत करता है।

बजट में कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों और मत्स्य पालन को प्राथमिकता दी गई है, किसान सहकारी समितियों और मूल्य संवर्धन पर जोर दिया गया है। यह ग्रामीण ऋण को मजबूत करने की पिछली पहलों पर आधारित है, जिसमें पैक्स को ग्रामीण समृद्धि के लिए बहु-सेवा केंद्र के रूप में देखा गया है। बजट का एक अन्य प्रमुख पहलू यह है कि इसमें सहकारी मत्स्य पालन क्षेत्र के लाभ के लिए देश में पांच एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। बजट में सब्सिडी वाले ऋण के माध्यम से आवास पर ध्यान केंद्रित करने से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को कम लागत और किफायती घर उपलब्ध कराने के लिए सहकारी आवास आंदोलन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने से पैक्स की विविध गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास को और बढ़ावा मिलता है।

Publication:	Agri 2047, Pg 3	Edition:	Online
Published Date:	February 06, 2024		

Budget 2024 Empowers Farmers, Boosts Rural Economy Through Cooperatives

https://www.agri2047.com/2024/02/06/budget-2024-empowers-farmers-boosts-rural-economy-through-cooperatives-2/

In line with Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of "Sahakar Se Samriddhi" (Prosperity through Cooperation), the Interim Budget 2024 prioritises initiatives to empower farmers through the cooperative sector.

The Budget presented in Parliament echoes the 54 major initiatives undertaken by the Ministry of Cooperation under the leadership of Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah.

The initiatives taken by the Ministry of Cooperation aim to strengthen PACS (Primary Agricultural Credit Societies) and primary cooperatives across the country, marking a significant milestone on the path to rural prosperity.

While the Budget rightly prioritises systemic inequality reduction, with a focus on the empowerment of women, youth, marginalized groups, and farmers through various socio-economic initiatives, it also provides a major boost to the cooperatives and rural economy.

Explaining the various aspects of the Budget, officials said continued support for Dairy Processing, brand building, marketing and Infrastructure Development Fund, Rashtriya Gokul Mission (RGM), and National Programme for Dairy Development (NPDD) strengthens the cooperative dairy sector.

The Government aims to increase Lakhpati Didis from 2 crore to 3 crore through self-help groups (SHGs) and has allocated a corpus of Rs One lakh crore for this purpose.

Since rural SHGs are funded by PACS, this presents a great opportunity for PACS to make an impact on the financial status of rural women by implementing it at the village level, officials said.

The budget prioritizes agriculture, rural areas, and fisheries, emphasizing farmer cooperatives and value addition. It builds on past initiatives to strengthen rural credit, with PACS envisioned as multi-service centers for rural prosperity.

Another major aspect of the Budget is that it proposes setting up five Integrated Aqua Parks in the country for the benefit of, amongst others, the cooperative fishery sector.

The cooperative housing movement will get a big boost for providing low-cost and affordable houses to low and middle-income families both in urban and rural areas due to the focus of the budget on Housing through subsidized loans.

Promotion of micro food processing further bolsters rural development through PACS diversified activities, the officials said.

To propel the rural economy, improving efficiency is the mantra here in the Budget. The budget proposal on a corpus of Rs. 1.00 lakh crore with a fifty-year interest-free loan on research and innovation in emerging domains could be a real game changer, particularly in the field of agriculture, modernization of the cooperative sector, rural development, and processing sector.

Finally, the budget even gave a brand new makeover to the meaning of GDP and FDI GDP stands for General Development and Performance and FDI is First Developed India.

LOCATIONS OF NCCT INSTITUTES

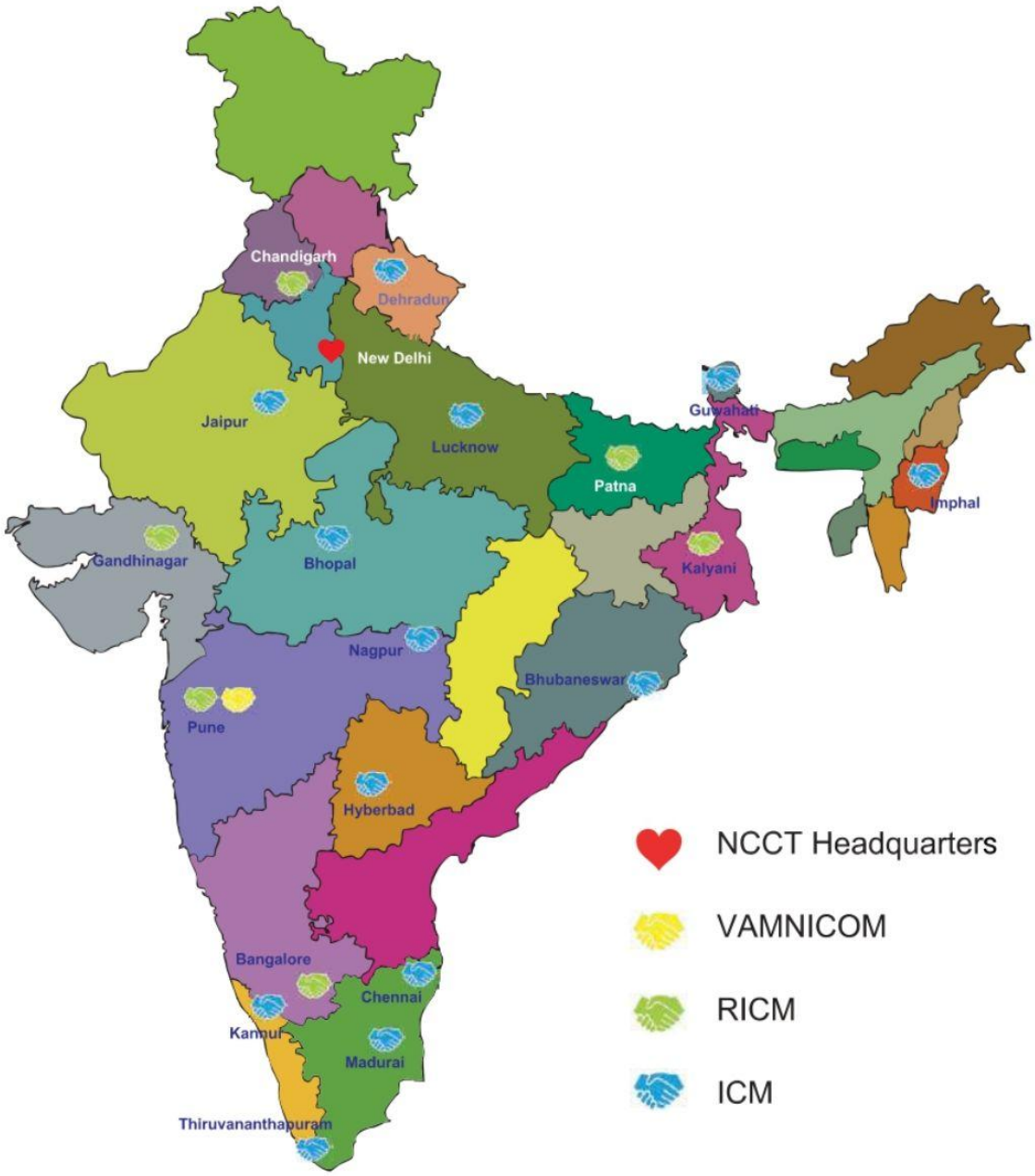

NATIONAL COUNCIL FOR COOPERATIVE TRAINING

(AN AUTONOMOUS SOCIETY PROMOTED BY MINISTRY OF COOPERATION, GOVERNMENT OF INDIA)

3, Siri Institutional Area (3rd Floor), August Kranti Marg, New Delhi-110016

011-41096510 secy-ncct@gov.in www.ncct.ac.in